

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम  
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ३१ फरवरी, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1696/अप्रैजल-देहरादून/ दिनांक 14.12.05 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून की राजीवनगर डोंडा पुनर्गठन पेयजल योजना अनु०लागत रु० 978.95 लाख एवं डोईवाला पुनर्गठन पेयजल योजना अनु०लागत रु० 499.99 लाख के प्राक्कलनों पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि कमशः रु० 780.60 लाख (रु० सात करोड़ अस्सी लाख साठ हजार मात्र) तथा रु० 390.60 लाख (रु० तीन करोड़ नब्बे लाख साठ हजार मात्र) अर्थात् कुल रु० 1171.20 लाख (रु० ग्यारह करोड़ एकहत्तर लाख बीसहजार मात्र) की लागत के प्राक्कलनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में निम्न विवरणानुसार कुल रु० 100.00 लाख (रु० एक करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रु० लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	जनपद देहरादून की राजीवनगर डोंडा पुनर्गठन पेयजल योजना	780.60	50.00
2	जनपद देहरादून की डोईवाला पुनर्गठन पेयजल योजना	390.60	50.00
	योग	1171.20	100.00

1- उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हरताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात् उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त की धनराशि अवमुक्त की जाय।

3— स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-87(1)/दस-97-17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष कुल सेन्टेज चोर्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि योजना में इससे अधिक सेन्टेज व्यय होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, का होगा।

4— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

7— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदुपरांत ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

9— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

10— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11— आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

12— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

12— यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

13— मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

14— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान सं०-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-01-नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजराहायता के नाम" डाला जायेगा।



15- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०- 44/XXVII(2)/2008 दिनांक 12 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)  
संयुक्त सचिव

पृ०सं० 367<sup>(१)</sup>/उन्तीस(2)/०४-2(60 पे०)/2006तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
10. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- ✓ 13. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)

उप सचिव

18/1/08